

आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में राज्यपालों द्वारा प्रतिवेदन

6157. श्री श्रीका माई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपालों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन प्रतिवेदनों में इन क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार लाने के सुझाव दिए गए हैं ;

(ग) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने पांचवी अनुसूची के पैराग्राफ 5(2) के अनुसरण में विनियमन बनाये हैं ;

(घ) यदि विनियमन नहीं बनाये गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यपालों को कोई निर्देश जारी किए हैं ?

गृहमंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकबभजा) :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपालों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है : —

राज्य	रिपोर्टों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
बिहार	10
गुजरात	9
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	9
उड़ीसा	10
राजस्थान	9

(ख) ये रिपोर्टें सामान्यतः राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का एक रिकार्ड होती हैं।

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं होते। अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों,

अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण विशेष रूप से भूमि हस्तान्तरण, ऋण भरतता, सहकारी के बारे में अधिनियम/विनियम/राजस्व संहिता विद्यमान हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बजाज स्कूटरों के वितरण के बारे में शिकायतें

6158. श्री सुन्दर शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बजाज कम्पनी द्वारा निर्मित दो पहिये वाले स्कूटरों के वितरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके वितरण पर अपना नियंत्रण रखने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणवीर चामना) : (क) जी हां।

(ख) स्कूटरों की बिक्री और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी, वितरण में अनियमितताओं के विशिष्ट आरोपों की उपर्युक्त कार्यवाही के लिए अथवा जांच व रिपोर्ट करने के लिए निर्माता के पास समुचित रूप से भेजा जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Paper Projects under the Hindustan Paper Corporation and their Annual Production Capacity

6159. SHRI DAULATSINHJI JADEJA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) the names of the projects manufacturing newsprint, pulp and paper under the Hindustan Paper Corporation Ltd. with their annual production during the last 3 years;

(b) whether any of the above projects has applied for expansion;

(c) if so, the decision taken by Government; and